The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] No. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27—मई 3, 2019 (वैशाख 7, 1941)

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27-MAY 3, 2019 (VAISAKHA 7, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची					
	पृष्ठ सं.	पृ	ष्ठ सं.		
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के		छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक			
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की		आदेश और अधिसूचनाएं	*		
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा		भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों			
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	347	(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय			
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के		प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को			
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की		छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक			
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों,		नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य			
पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में		स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी			
अधिसूचनाएं	491	प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत			
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों		के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित			
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में		होते हैं)	*		
अधिसूचनाएं	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक			
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी		नियम और आदेश	*		
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,		भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और			
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1043	महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल			
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध			
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों		और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई			
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	अधिसूचनाएं	927		
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और			
के बिल तथा रिपोर्ट	*	डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*		
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन			
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*		
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों			
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक		द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन			
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और		और नोटिस शामिल हैं	17		
उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों			
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों		द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	683		
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों			
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		को दर्शाने वाला सम्पूरक	*		
*आंकडे प्राप्त नहीं हुए।					

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the	INU.	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative	*
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court		texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
Part I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1043	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by	
Part II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations Part II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi	*	Attached and Subordinate Offices of the Government of India	927
language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	Part III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
Committee on Bills	*	Part III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the		Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	17
Administration of Union Territories) PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory	*	Part IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	683
Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and	
(other than the Ministry of Defence) and		Deaths etc. both in English and Hindi	*

^{*}Folios not received.

भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पोत परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2019

आदेश

सं. एसवाई—19014 / 14 / 2018—एसबीआर—332328——पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2017 को भारत के राजपत्र के भाग—I खण्ड—I में प्रकाशित पोतभंजन संहिता (संशोधित), 2013 के पैरा 8.4.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार एतद्द्वारा पोतभंजन संहिता (संशोधित), 2013 में निम्नानुसार संशोधन करता है:——

(i) पैरा 5.2.2 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाए :--

''5.2.2 विसंदूषण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जीपीसीबी के दौरे के समय डीआईएसएच कार्मिक भी जीपीसीबी कार्मिकों के साथ रहेंगे, और उचित समझे जाने पर, जीपीसीबी द्वारा विसंदूषण प्रमाणपत्र जारी करने से पहले डीआईएसएच कार्मिकों द्वारा ज्वलनशील / दहनशील सामग्री को हटाने की अनुमति दी जाएगी।''

के स्थान पर :

"5.2.2 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विसंदूषण प्रमाणपत्र जारी करने से पहले राज्य समुद्री बोर्ड / पत्तन प्राधिकरण द्वारा तेल एवं खुली सामग्रियों को हटाने की अनुमित के साथ ही कोल्ड ऑपनिंग के माध्यम से ज्वलनशील और दहनशील सामग्री को हटाने की अनुमित भी दी जाएगी।"

पढा जाए :

दशरथ प्रसाद निदेशक

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2019

संकल्प

सं. ई-11016/01/2017-हिंदी(पार्ट)--आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्ववर्ती शहरी विकास मंत्रालय एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) के दिनांक 20 मार्च, 2015 के संकल्प सं. ई-11016/01/2014-हिंदी के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इसका कार्यकाल 19 मार्च, 2018 को समाप्त हो गया था। बाद में इसका कार्यकाल दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 के समसंख्यक संकल्प द्वारा एक वर्ष अर्थात् 19 मार्च, 2019 तक बढ़ाया गया था।

अब माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से इसका कार्यकाल एक वर्ष की और अवधि अर्थात् 19 मार्च, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

> नंदिता गुप्ता संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 27th March 2019

ORDER

No. SY-19014/14/2018-SBR-332328—In exercise of the powers conferred by para 8.4.1 of the Shipbreaking Code (Revised), 2013, published by the Ministry of Shipping vide order dated 2nd February, 2017 in Gazette of India Part I-Section 1 dated 18.02.2017, the Government of India in the Ministry of Shipping hereby amends the Shipbreaking Code (Revised), 2013, as follows:

(i) Para 5.2.2 shall be amended to read as under:—

For:

"5.2.2 DISH officials with accompany the GPCB officials, at the time of visit for issuing decontamination certificate by GPCB, and if considered appropriate, DISH officials may permit removal of fire prone/combustible material before issuance of decontamination certificate by GPCB."

Read:

"5.2.2 Removal of fire prone and combustible materials by cold opening may be allowed by State Maritime Board/Port Authority along with permission of removal of Oils and Loose Materials, before issuance of Decontamination Certificate by the State Pollution Control Board".

DASHRATH PRASAD Director

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

New Delhi, the 18th March 2019

RESOLUTION

No. E-11016/01/2017-Hindi(Part)—Hindi Advisory Committee of Ministry of Housing and Urban Affairs was constituted vide Resolution No. E-11016/1/2014-Hindi dated 20th March, 2015 of Ministry of Housing and Urban Affairs (erstwhile Ministry of Urban Development and Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation). Its tenure ended on 19th March, 2018. Later on vide resolution of even number dated 17th December, 2018, its tenure was further extended till 19th March, 2019.

Now with the approval of Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Housing and Urban Affairs, its tenure is further extended for a period of one year i.e. till 19th March, 2020.

NANDITA GUPTA Joint Secretary